

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 2008—मई 2, 2008 (वैशाख 6, 1930) No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26, 2008—MAY 2, 2008 (VAISAKHA 6, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-भाग |--खण्ड-1--(रक्षा पंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेश्राँ तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधि-स्चनाएं -(रक्षा पंत्रालय की छोडकर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी आधिकारियों की निपुष्तितयों, पदोन्नतियों. छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं थाग |--खण्ड-3-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पी और असंविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिस्चनाएं भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदीन्तियों, छद्रियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 457 भाग 🍴 -- खण्ड-। -- अधिनियम, अध्यादेश और विनियम भाग 11— खण्ड- 1 क-- अधिनियमी, अध्यादेशी और विनियमी का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ भाग [[—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयको पर प्रथर समितियाँ के बिल तथा रिपोर्ट भाग !]—खण्ड-3—डप खण्ड (i) - भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोडकर) और केन्द्रीय प्रधिकरणों (संध शास्तित क्षेत्रों के प्रशासनों को ब्रोडकर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपांबधियां आदि भी शामिल हैं भाग [[—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयाँ (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और के दीय प्राधिकरणीं (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनीं को झेड़कर) द्वारा जारी किए गए साविधिक आदेश और अधिस्चनाएं.....

सूची	
भाग]]—-खण्ड-3—-उप खण्ड (iii)भारत सरकार के मंत्रालयाँ (श्रिसमें रक्षा मंत्रालय मी श्रामिल हैं) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित खेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए स्वासन्य सांविधिक नियमों और सांविधिका आदेशों (जिनमें साधान्य स्वरूप की उपविधियां	
भी ऋमिल हैं) ने हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे	
पार्खें को छोड़कर जो धरत के राजपन्न के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकारित होते हैं)	•
भाग II — खण्ड-4रका मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंश्वक और पहालेखायरीक्षक, सेच लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की पई	
अधिसूचनाएँ भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टी और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ और	3095
नोटिस भाग 111—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन	165
अयवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ····· भाग III— खण्ड- 4— विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक	ar 🖲
निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं,	1311
भाग IVगैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों	****
द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	87
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दीनों में जन्म और मृत्यु के	
आंकड़ों को दर्शने बाला सम्पूरक	*

CONTENTS

Part I—Section 1—Notifications relating to Non-		than the Administration of Union	
Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries		Territories)	*
of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the		PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts,	
Supreme Court	287	published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General	
PART I—Section 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India		Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the	
(other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	399	Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration	
PART I-Section 3-Notifications relating to		of Union Territories)	*
Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	. 1	PART II—Section 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	
PART 1—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the		PART III—Section I—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service	
Ministry of Defence	457	Commission, the Indian Government	
PART II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations	W	Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3095
PART II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi		a.t	
Regulations	•	PART III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to	122
PART II—Section 2—Bills and Reports of the Select		Patents and Designs	165
Committee on Bills	*	PART III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief	
PART II—Section 3—Sub-Section (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-		the authority of Chief	
laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than		Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders. Advertisements and Notices issued by	
the Administration of Union		, Statutory Bodies	1311
Territories)	*	PART IV-Advertisements and Notices issued by	
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory		Private Individuals and Private	0.5
Orders and Notifications issued by the		Bodies	87
Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births	
(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		and Deaths etc. both in English and	

^{*}Folios not received.

भाग I—खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं] [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

खान मंत्रा*लय* नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2008 <u>संकल्प</u>

सं. 11(39)/2007-खान-1 जीएसआई के कार्यकरण की पूर्ण रूप से समीक्षा करने तथा संगठन की प्रौद्योगिकी एवं मानव शक्ति संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, उभरती हुई शुनौतियों का सामना करने की इसकी क्षमता का आकलन करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन करने से संबंधित दिनांक 7 जनवरी, 2008 के संकल्प संख्या -11(39)/2007-खान-1 में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार एतद्द्वारा एचपीसी की सरचना में संशोधन करती है। संशोधित संरचना निम्नानुसार होगी:

i.	श्री एस विजय कुमार, अपर सचिव	अध्यक्ष
	खान मंत्रालय	
2.	डा० प्रीतम सिंह,	
	भैनेजमेंट डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट , गुडगांव	सदस्य
3.	डा० (श्रीमती) मालती गोयल	
	पूर्व सलाहकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
4.	श्री संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव एवं	da
	वित्तीय सलाहकार, खान मंत्रालय	सदस्य
	(वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि)	
5.	डा० रसिक रवीन्द्र, निदेशक	सदस्य
	राष्ट्रीय अंटार्टिक एवं	
	महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा	
6.	श्री एल.पी.सोनकर, सलाहकार (खनिज)	सदस्य
	योजना आयोग (योजना आयोग के प्रतिनिधि)	
7	डा0 नागेश सिंह, सलाहकार, पीएएमडी.	सदस्य
	योजना आयोग	
8.	श्री आर.के.शर्मा, महासंचिव	सदस्य
	फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (फिमी)	
9.	डा० पी एन राजदान, उप-महानिदेशक	सदस्य
7.0	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ	

10.	डाO बलराम चहोपाध्याय, उप-महानिदेशक	सदस्य
11.	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,कोलकाता श्री इशराक अहमद, सलाहकार	सहयोजित सदस्य
12.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय डाO के अय्यासामी, निदेशक (तकनीकी)	सहयोजित सदस्य
13.	े खान <i>पंत्रालय</i> श्री सुरेश किशनानी,	सदस्य सचिव
	निदेशक , खान मंत्रालय	

एचपीसी के विचारार्थ विषय तथा उनसे संबंधित प्रावधान वही रहेगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को दी जाए। एस. विजय कुमार अपर सचिव

> पानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

मई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2008

संकल्प

सं. 3-6/2008-टो.एस.-V.--

माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय की विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने दिनाक 21 जनतरी, 2004 को भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-111, धारा -4) प्रकाशित अधिसुचना संख्या 37-3/लीगल/2004 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालय विभागों में प्रवासी भारतीयों, विदेशी राष्ट्रिकों और भारतीय मूल के लोगों के इंजीनियरी और प्रौक्षेणिको, यास्तुकला और नगर आयोजना, फार्नेसी, अनुप्रयुक्त कलाओं, एम.बी.ए., एम.सी.ए., होटल प्रबंध और कैटरिंग प्रौद्योगिकी आदि में डिप्लोमा, डिग्री और रमातकोत्तर तक्षमीकी पाठ्यकर्मों में दक्षिलों के संबंध में विस्तृत विकियम जारी किए हैं। इन विविधमों के तहत कुल सीटों का 15 प्रतिशत (अनुमोदित दाखिला श्रमता) को खाड़ी देशों में भारतीय कर्मचारियों के बच्चों सहित ऊपर उत्लिखित श्रेणियों हेतु अधिसंख्य आधार पर विभिन्न विषयों में आरक्षित किया गया है।

उपर्युक्त अधिसूचनाओं के मद्देवजर विदेशी राष्ट्रिकों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की वर्तमान परंपरा को समाप्त करने, समिवश्वविद्यालयों अथवा सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं सहित स्ववित्त पोषित संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालय विभागों में प्रवासी भारतीयों, भारतीय मूल के लोगों आदि को अवर स्नातक और स्नातकोतार स्तर पर ऊपर उद्गिलिक तकनीकी पाउपक्रम करने की अनुभति देने का प्रश्न भारत सरकार के विज्ञासधीन था। सावधानीपूर्वक विचार करने के कर यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त श्रेणियों के खत्रों को भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई में ऐसे पाठ्यक्रम करने के लिए सरकार से अनावतित प्रमाण पत्र की आदृश्यकता नहीं होजी और उनका दाखिला समय-समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना

हारा अभिशासित होगा। तथापि, निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थानों तथा राष्ट्रीय औद्योगिक इंनीनियरी संस्थान, मुम्बई का यह कर्ताव्य होगा कि वे उथल वर्ग के दाखिल छत्रों के ब्यौरे की सूधी (देश-वार) जिसमें उनके पाठ्यक्रमों का विवरण, पासपोर्ट विवरण, लिए जाने वाले शुरूक एवं भारत में आवासीय प्रते की, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (तकनीकी अनुभाग-ए), शास्त्री भवन, नई दिल्ली को भेज दे। यह सूची विदेश मंत्रालय(छत्र प्रकोष्ठ) अकबर भवन, नई दिल्ली के साथ-साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह अधिसूचना पहले से ही दाखिल या शैक्षिक सन्न 2008-09 तथा इससे आगे से प्रभावी होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति इन्हें भेज दी जाए:

- निदेशक, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, क्षोद्यीकोड, लखनऊ, हंदौर एवं आर.जी. आई.आई.ग्रम. शिलांग।
- ब्रिदेशक, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई।
- अखिल भारतीय तकजीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली।
- सभी भारतीय विश्वविद्यालयों /शमविश्वविद्यालयों , के कुलपिते ।
- सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशक।
- सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशक।
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, वई दिल्ली।
- 10. विदेश में सभी भारतीय मिशन।
- 11. मारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- 12. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रमुख संविद।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प, सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

कल्पना सिंह उप-सचिव

MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 27th March 2008

RESOLUTION

No.11(39)/2007-M.I. In partial modification of the Resolution No. No.11(39)/2007-M.I dated 7th January, 2008, constituting a High Powered Committee (HPC) to thoroughly review the functioning of the Geological Survey of India (GSI), and assess its capacity to meet the emerging challenges taking into account the organisation's technological and manpower resources, the Government hereby modifies the composition of the HPC. The revised composition will be as under:

	osition will be as under:	the IPC. The revi
6)	Shri S. Vijay Kumar, Additional Secretary, Ministry of Mines	- Chairman
(ii)	Dr. Pritam Singh, Professor of Eminence, Management Development Institute, Gurgaon	- Member
(iii)	Dr. (Mrs.) Malti Goel, Ex- Adviser, Ministry of Science & Technology	- Member
(iv)	Shri Sanjiv Mittal, Joint Secretary & Financial Adviser, Ministry of Mines. (Representative of the Ministry of Finance)	- Member
(v)	Dr. Rasik Ravindra, Director, National Centre for Antarctic & Ocean Research, Goa.	- Member
(vi)	Shri L.P. Sonkar, Adviser (Minerals), Planning Commission (Representative of the Planning Commission)	- Member
(vii)	Dr. Nagesh Singh, Advisor, PAMD, Planning Commission.	- Member
(viii)	Shri R.K. Sharma, Secretary General, Federation of Indian Mineral Industries (FIMI)	- Member
(ix)	Dr. P.N. Razdan, Dy. Director General, Geological Survey of India, NR, Lucknow	- Member
(x)	Dr. Balaram Chattopadhyay, Dy. Director General, Geological Survey of India, Kolkata	- Member
(xi)	Shri Ishraq Ahmed, Adviser, Ministry of Science & Technology	- Co-opted Member

Director (Technical).

Shri Suresh Kishnani, Director, Ministry of

- Co-opted Member

- Member-Secretary

(xii)

Dr. K. Ayyasami,

Ministry of Mines

Mines.

The terms of reference of the HPC and other provisions relating thereto will remain the same.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

S. VIJAY KUMAR Additional Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 9th April 2008

RESOLUTION

No. 3-6/2008-TS-V --

In pursuance of various judicial pronouncements of the Hon'ble Supreme Court of India, the All India Council for Technical Education (AICTE), vide Notification No.37-3/Legal/2004 dated 21st January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III Sec.4) on 26th February 2004, had issued detail regulations concerning admission of Non-Resident Indians (NRIs), Foreign Nationals (FN) and persons of Indian Origin (PIO) etc in all institutions/University Departments approved by AICTE offering technical courses leading to Diploma, Degree and Post-Graduate Degree in Engineering & Technology, Architecture & Town Planning, Pharmacy, Applied Arts, MBA, MCA, Hotel Management & Catering Technology etc. Under these regulations, fifteen percent (15%) of seats (approved intake capacity) have been reserved across different disciplines on supernumerary basis for the abovementioned categories of students including the children of Indian workers in the Gulf Countries.

In the light of the above notification, the question of doing away with the present practice of issuing No Objection Certificate (NOC) to the Foreign Nationals, NRIs, PlOs etc. for pursuing the above mentioned technical courses at under-graduate and post graduate levelin Self-Financing Institutions or University Departments including Deemed Universities or Government funded Institutions was under consideration of the Government of India. After careful consideration, it has been decided that a NOC from the Government would no longer be required in respect of the above categories of students for pursuing such courses in Indian Institutes of Management (IIMs) and National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai and their admission shall be governed by the above notification as amended from time to time. However, it shall be duty of Directors, IIMs and NITIE, Mumbai admitting above categories of students, to furnish a complete list of admitted students (country wise) every year by 30th September, giving details of their courses, passport particulars, fee being charged and the residential addresses in India to the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, (Technical Section-V), Shastri Bhavan, New Delhi. This list should also be furnished to AICTE as well as to the Ministry of External Affairs (Students Cell), Akbar Bhavan, New Delhi. This would be applicable for admissions already made or to be made from the Academic Session 2008-2009 onwards.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to:-

- Directors, Indian Institutes of Management (IIMs), Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Kozhikode, Lucknow. Indore and RGIIM, Shiltong
- 2. Director, National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai,
- 3. All India Council for Technical Education, New Delhi.
- 4. University Grants Commission, New Delhi,
- 5. Association of Indian Universities, New Delhi,
- Vice-Chancellors of all Indian Universities/Deemed Universities,
- 7. Directors of all Indian Institutes of Technology (IITs),
- 8. Directors of all National Institutes of Technology (NITs),
- 9. Indian Council for Cultural Relations, New Delhi,
- 10. All the Indian Missions abroad,
- 11. All the Ministries/Departments of the Government of India,
- 12. Chief Secretaries of all States & Union Territories.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

KALPANA SINGH Deputy Secretary